हिन्दी साप्ताहिक

PRGI No:- UABIL/25/A3383

उत्तराखण्ड अभ्युदय

♦वर्ष -02 ♦ अंक-37 ♦देहरादून - रविवार 19 जुलाई 2026 ♦पृष्ठ : 4 ♦मूल्यः 1/-15

वेड इन उत्तराखंड अभियान स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को देगा नई गति : मुख्यमंत्री

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मसूरी-देहरादून मार्ग स्थित पुनर्नवा वेलनेस रिजॉर्ट, किमाड़ी में इंटरनेशनल कन्वेन्शन ऑफ इवेंट इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित ग्रेस हिन्दुस्थान 2.0 उत्तराखण्डश राष्ट्रीय वेडिंग प्रोफेशनल्स सम्मेलन में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने देशभर से आए वेडिंग प्लानर्स, इवेंट विशेषज्ञों, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों तथा सभी अतिथियों का देवभूमि उत्तराखंड में स्वागत करते हुए कहा कि यह सम्मेलन राज्य में पर्यटन, विशेषकर वेडिंग टूरिज्म के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी दो दिनों तक आयोजित इस सम्मेलन में पर्यटन, वेडिंग और इवेंट उद्योग से जुड़े विशेषज्ञों के विचार-मंथन से उत्तराखंड में पर्यटन विकास को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने इस आयोजन के लिए इंटरनेशनल कन्वेन्शन ऑफ इवेंट इंडस्ट्रीज की पूरी टीम तथा पुनर्नवा वेलनेस रिजॉर्ट के संस्थापक आचार्य आशीष सेमवाल को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि इस मंथन के सकारात्मक परिणाम राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रध नमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्वेड इन उत्तराखंडष की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वेडिंग और इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े सभी विशेषज्ञों के सहयोग से उत्तराखंड को देश और दुनिया के प्रमुख वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में विवाह केवल सामाजिक आयोजन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का पवित्र मिलन माना जाता है। देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत ऐसे पावन अवसर को और अधिक दिव्य बना देती है। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह स्थल त्रियुगीनारायण मंदिर जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर उत्तराखंड को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विशिष्ट पहचान प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार त्रियुगीनारायण, ओंकारेश्वर (ऊखीमठ), रामनगर, टिहरी, मसूरी सहित अन्य उपयुक्त स्थलों को विश्वस्तरीय डेस्टिनेशन वेडिंग केंद्रों के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग केवल होटल और रिसॉर्ट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इससे स्थानीय कारीगरों, लोक कलाकारों, होमस्टे संचालकों, टैक्सी चालकों तथा अनेक छोटे व्यवसायों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और आय के नए अवसर प्राप्त होते हैं। इसी कारण राज्य सरकार वेडिंग टूरिज्म को स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम मानते हुए आगे बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आने वाले पर्यटक केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि यहां की संस्कृति, अध्यात्म और आत्मीयता का भी अनुभव अपने साथ लेकर जाएं, इसी उद्देश्य से पर्यटन के विविध आयामों को विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रकृति, संस्कृति, अध्यात्म और वेलनेस का अद्भुत संगम है, जहां लोगों को एक संपूर्ण पर्यटन अनुभव प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुनर्नवा वेलनेस रिजॉर्ट इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और आधुनिक सुविधाओं का समन्वय कर विश्वस्तरीय वेलनेस अनुभव उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वेडिंग टूरिज्म के साथ-साथ स्पिरिचुअल और वेलनेस टूरिज्म को भी समान रूप से बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार केदारखंड और मानसखंड के मंदिर क्षेत्रों के विकास एवं सौंदर्यीकरण के साथ हरिद्वार-ऋषिकेश कॉरिडोर, विवेकानंद कॉरिडोर, गोल्ज्यू कॉरिडोर, यमुना कॉरिडोर तथा शारदा कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। साथ ही शीतकालीन यात्रा की शुरुआत कर वर्षभर पर्यटन को गति देने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में एक-एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है, जिससे योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और आध्यात्मिक पर्यटन को नई मजबूती मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड आज कानून-व्यवस्था, सुशासन और निवेश अनुकूल नीतियों के कारण देश के सबसे भरोसेमंद राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सड़क, रेल और रोपवे आधारित ट्रिपल आर कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने पर विशेष बल दे रही है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, विभिन्न रोपवे परियोजनाओं, जौलीग्रांट एवं पंतनगर हवाई अड्डों के विस्तार तथा प्रदेश के सभी जिलों में हेलीपोर्ट विकास जैसे कार्य पर्यटन को नई गति प्रदान करेंगे और पर्यटकों की पहुंच को और अधिक सुगम बनाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को व्यवहारिक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंगल विंडो क्लीयरेंस व्यवस्था के माध्यम से निवेशकों, वेडिंग प्लानर्स और इवेंट आयोजकों को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित सभी विशेषज्ञों एवं निवेशकों से उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए अपने सुझाव साझा करने का आग्रह करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से उत्तराखंड को विश्व के सर्वोत्तम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने का संकल्प अवश्य साकार होगा। इस अवसर पर इंटरनेशनल कन्वेन्शन ऑफ इवेंट इंडस्ट्रीज के पदाधिकारी, पुनर्नवा वेलनेस रिजॉर्ट के संस्थापक आचार्य आशीष सेमवाल, देशभर से आए वेडिंग प्लानर्स, इवेंट एवं पर्यटन उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, विभिन्न उद्यमी, निवेशक तथा बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

पीएम आवास योजना के कार्यों में देरी पर सचिव आवास हुए सख्त, धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित आवासीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए मंगलवार को सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न जिलों में प्रध नमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) घटक के अंतर्गत निर्माण कार्य कर रही कार्यदायी संस्थाओं और विकासकों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई परियोजनाओं में निर्माण कार्यों की धीमी गति सामने आने पर सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रध नमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं में से एक है और इसके कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास धीरेन्द्र रावत, अधिशासी अभियंता विनोद कुमार चौहान, अधिशासी अभियंता सुनील कुमार, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ रोहित रंजन सहित विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े विकासकों एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे।बैठक के दौरान सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने परियोजनावार प्रगति की समीक्षा करते हुए पाया कि कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य निर्धारित गति से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर उन्होंने संबंधित विकासकों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि लाभार्थियों को समय पर आवास उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई परियोजनाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, ऐसे में शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कर लाभार्थियों को जल्द से जल्द मकानों का कब्जा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने सभी विकासकों को परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद सभी विकासकों और कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत संचालित सभी परियोजनाओं के निर्माण कार्य 15 अगस्त 2026 से पूर्व पूर्ण किए जाएं। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समयसीमा तक कार्य पूरे नहीं किए जाते हैं तो संबंधित विकासकों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी पूरी तरह संबंधित कार्यदायी संस्था और विकासक की होगी।

बैठक में सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) अधिकारियों को ध ौलास आवासीय परियोजना के अंतर्गत आवंटन संबंधी सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन सभी परियोजनाओं की समीक्षा की गई जो पूर्णता के अंतिम चरण में हैं। अधिकारियों को लाभार्थियों को मकानों का हस्तांतरण (की-हैंडओवर) समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां अभी से पूरी करने को कहा गया।राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में विभाग लगातार परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहा है ताकि निर्माण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लाभार्थियों को जल्द राहत दी जा सके। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जहां सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया कि विकास कार्यों में देरी अब किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना केवल एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि हजारों परिवारों के अपने घर के सपने से जुड़ी योजना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक पात्र लाभार्थी को समय पर आवास उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं में कार्यों की गति धीमी है, वहां तत्काल सुधार लाया जाए। सभी विकासकों को तय समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने होंगे, अन्यथा अनुबंध के अनुरूप कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को भी नियमित निगरानी और स्थलीय निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि किसी प्रकार की देरी न हो और लाभार्थियों को जल्द से जल्द उनके आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

सम्पादकीय

होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन

गृहवासे पर्यटनं च उत्तराखण्डे नवं बलम्।
दशसहस्र गृहाणां लक्ष्यं राज्येन कल्पितम्।।
धाम-भीडं महाघं च त्यक्त्वा पर्यटका: इत:।
ग्राम्यं जीवनं प्रकृतिं च द्रष्टुं कान्तारमागता:।।

अर्थात्

उत्तराखंड में होम स्टे और ग्रामीण पर्यटन नई शक्ति बन रहे हैं। राज्य ने इस वर्ष 10 हजार होम स्टे का लक्ष्य रखा है। चारधाम की भीड़ और महंगे होटलों को छोड़कर पर्यटक अब गांवों का जीवन और प्रकृति का सानिध्य पाने आ रहे हैं।

इसका सबसे बड़ा लाभ पलायन पर रोक और स्वरोजगार है। पहाड़ के युवा अब दिल्ली-मुंबई न जाकर अपने घर को होम स्टे बनाकर रोजगार कमा रहे हैं। इससे महिलाओं को आय मिली है और स्थानीय भोजन, ऊनी उत्पाद, लोक कला व जैविक खेती को वृहद बाजार मिला है। मुनस्यारी, चोपता, बिनसर जैसे गांव नए पर्यटन केंद्र बनकर उभरे हैं।

यदि मार्केटिंग,कौशल प्रशिक्षण और सस्ता लोन मिले ,तो होम स्टे पहाड़ों को आत्मनिर्भर बना सकता है।संवृद्धि और खुशहाली घर घर महकने लगेगी।

देवभूमि उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहते हुए पर्यटन का सतत विकास हो, यही कामना है।

जय देवभूमि उत्तराखंड!!जय भारत!!

डॉ.गार्गी मिश्रा

मोदी का चेहरा कितना फर्क डालेगा?

हरिशंकर व्यास

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में दो राज्य-तेलंगाना और मिजोरम ऐसे हैं, जहां भाजपा कभी मजबूत नहीं रही है। न विधानसभा चुनावों में उसकी चुनौती को गंभीरता से लिया गया है। इस बार भी दोनों राज्यों में भाजपा लड़ रही है लेकिन वह किसी के लिए चुनौती नहीं है। हां, बाकि तीन राज्यों में वह बहुत गंभीरता से पहले भी लड़ती रही है और अब भी लड़ रही है। इस बार फर्क यह है कि अब तक इन राज्यों में भाजपा प्रादेशिक क्षत्रपों के नाम और काम पर लड़ती थी, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने खुद ऐलान किया है कि इस बार के चुनाव में कमल का फूल ही चेहरा है। मध्य प्रदेश में तो प्रचार के जो रथ निकले हैं उन पर नारा लिखा है- मोदी के मन में बसता है एमपी और एमपी के मन में मोदी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के लोगों के नाम एक खुली चि;ी भी लिखी है। तभी सवाल है कि मोदी का चेहरा चुनाव में कितना फर्क डालेगा?

मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव कभी भी बड़े अंतर वाला नहीं रहा है। पिछली बार यानी २०१८ में जब कांग्रेस पार्टी जीती थी, तब भी कांग्रेस और भाजपा के वोट में एक फीसदी से कम का अंतर था और वोट के लिहाज से भाजपा बड़ी पार्टी थी। पिछला चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़ा गया था, जो १२ साल से ज्यादा समय से लगातार मुख्यमंत्री थे। इसके बावजूद पूरे राज्य में उनके खिलाफ नाराजगी की कोई लहर नहीं दिख रही थी। यह जरूर हो रहा था कि प्रचार में राम मनोहर लोहिया का यह नारा सुनने को मिला था कि तवे पर रोटी को उलटते-पलटते रहना चाहिए नहीं तो रोटी जल जाती है। तभी ऐसा लगा कि लोगों ने सिर्फ बदलाव के लिए बदलाव कर दिया और कांग्रेस को भाजपा से ज्यादा सीटें आ गईं। पांच साल बाद भी हालात बहुत नहीं बदले हैं।

शिवराज के खिलाफ अब भी कोई नाराजगी की लहर नहीं है लेकिन भाजपा आलाकमान ने खुद ही उनकी नैतिक सत्ता कमजोर कर दी है। उनके नाम और काम पर चुनाव लडने की बजाय भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के नाम और काम पर लड़ रही है। अगर मोदी का नाम भाजपा के पारंपरिक वोट में एक फीसदी का भी इजाफ कर दे तो तस्वीर बदल जाएगी। ध्यान रहे पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जो ११४ सीटें जीती थीं उनमें ४० सीटें ऐसी थीं, जिन पर वह १० हजार से कम वोट जीती थी और भाजपा ने १०९ में ४४ सीटों पर १० हजार से कम अंतर से जीत दर्ज की थी। कम अंतर से जीत-हार वाली इन ८४ सीटों पर जो समीकरण बनेगा उससे मध्य प्रदेश का नतीजा तय होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपना जादू चला कर इन सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी ओर एकजुट होकर लड़ रही कांग्रेस शिवराज को किनारे किए जाने का फायदा मिलने की उम्मीद में है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा के बीच पिछले चुनाव में एक फीसदी से थोड़े ज्यादा वोट का अंतर था। कांग्रेस को ३९.३ और भाजपा को ३८.०८ फीसदी वोट मिले थे। इतने भर से २७ सीटों का अंतर आ गया था। पिछली बार भाजपा वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ी थी। वे पांच साल से मुख्यमंत्री थीं। इस वजह से उनकी सरकार के खिलाफ एंटी इन्कम्बैंसी भी थी। दूसरे राजस्थान में पांच साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। १९९३ के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। यह बात कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जाती है। फिर भी उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी साल में बहुत मेहनत की है और अनेक बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। लोक लुभावन घोषणाओं और लाभार्थी वोट के दम पर गहलोत कड़ी टक्कर देने की उम्मीद कर रहे हैं। उनको भी प्रदेश के किसी नेता से नहीं लडना है। उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। गहलोत पिछड़ी जाति का दांव भी चल रहे हैं और चुनाव की घोषणा से दो दिन पहले जातीय गणना की अधिसूचना जारी कर दी। लेकिन दूसरी ओर मोदी भी अपने को पिछड़ा नेता बता कर ही प्रचार कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्यों में कांग्रेस के मजबूत प्रादेशिक क्षत्रपों का मुकाबला प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। मोदी ने जान-बूझकर कांग्रेस के क्षत्रपों से अपना मुकाबला बनाया है तो निश्चित रूप से उनके पास कुछ दांव होंगे, जिन्हें चुनाव प्रचार में आजमाया जाएगा। लेकिन इन तीनों राज्यों के राजनीतिक इतिहास और मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि मोदी और अमित शाह ने बड़ा जोखिम लिया है। लोकसभा चुनाव से पहले अगर इन तीनों राज्यों में या तीन में से दो राज्य में कांग्रेस जीतती है तो वह भाजपा को बड़ा झटका होगा।

कारोबारी संसार की घनचक्करी भूलभुलैया

पंकज शर्मा

मसला है कथित तौर पर पैसे ले कर लोकसभा में सवाल पूछने का। आरोप है कि महुआ ने उद्योगपति गौतम अडानी के कामकाज से संबंधित बहुत-से सवाल संसद में पूछे। ज्इसलिए महुआ मोइत्रा कितनी ही पाक-दामन हों, उन पर लगे छींटे हंगामा मचा रहे हैं।ज् उन्हें तो अग्निपरीक्षा दे कर ही खुद को पवित्र साबित करना होगा। इस समूचे प्रसंग में हमारे-आपके लिए सबसे बड़े सुकून की बात यह है कि महुआ तो कैसे गंगा नहाएंगी, वे जानें, मगर इस पृथ्वी पर कोई भी अग्निकुंड ऐसा नहीं है, जिस से गुजर कर अडानी अपने को निर्दोष सा. बित कर पाएं।

इस कहानी में चार अहम किरदार हैं। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य महुआ मोइत्रा, हीरानंदानी समूह के मालिक निरंजन हीरानंदानी के पुत्र दर्शन, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे और कारोबारी दुनिया पर निगाह रखने वाली पत्रकार सुचेता दलाल। मसला है कथित तौर पर पैसे ले कर लोकसभा में सवाल पूछने का। आरोप है कि महुआ ने उद्योगपति गौतम अडानी के कामकाज से संबंधित बहुत-से सवाल संसद में पूछे। उन्होंने इसके लिए दर्शन हीरानंदानी से कई फायदे लिए। इस आधार पर महुआ से इस्तीफे की मांग की जा रही है।

अब एक-एक कर इन चार किरदारों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ४९ बरस की महुआ कोलकाता में अपनी आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका चली गईं। वहां के मशहूर विश्वविद्यालयों में आर्थिक विषयों की पढ़ाई की और वहीं विश्व प्रसिद्ध निजी बैंक और संपत्ति प्रबंधन कंपनी जे. पी. मॉर्गन में नौकरी करने लगीं। २००९ में जब महुआ ने भारत की राजनीति में प्रवेश के लिए नौकरी छोड़ी तो वे मॉर्गन में उपाध्यक्ष थीं। आमतौर पर आठ से दस साल काम करने वाला व्यक्ति इस पद तक पहुंच जाता है।

देश वापस आने के बाद महुआ ने युवा कांग्रेस में काम करना शुरू किया। युवा कांग्रेस के 'आम आदमी का सिपाही' कार्यक्रम में काम करते हुए उन्होंने साल भर के भीतर ही अपनी अच्छी पहचान बना ली। कांग्रेस पार्टी में तरक्की की ध ीमी चाल महुआ को रास नहीं आ रही थी। सो, उन्होंने ममता बनर्जी की तरफ अपने कदम बढ़ाए और तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गईं। २०१६ में ममता ने उन्हें विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी दे दी और जीत कर वे विधायक बन गईं। २०१९ के चुनाव में उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। सो, वे चुन कर संसद में आ गईं।

कहानी के दूसरे किरदार दर्शन हीरानंदानी दुबई में रहते हैं। भवन निर्माण वगैरह से जुड़े काम करने वाले हीरानंदानी समूह का २०-२५ हजार करोड़ रुपए का कारोबार है। दर्शन के दादा यानी निरंजन के पिता लखूमल कान-नाक-गला डॉक. टर थे। उन्हें पद्मभूषण सम्मान भी मिला था। निरंजन चार्टर्ड एकाउंटेंट थे। उन्होंने भवन निर्माण के कारोबार की शुरुआत कोई चार दशक पहले की थी। अब उनका समूह दुनिया की सौ सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। बेटे दर्शन के अलावा उनकी एक बेटी भी है ख्र प्रिया। दर्शन का विवाह दिल्ली के व्यवसायी प्रदीप झालानी की बेटी नेहा से हुआ है। प्रिया की शादी लंदन में व्यवसाय कर रहे साइरस वंद्रेवाला से हुई है।

पैसे ले कर सवाल पूछने का आरोप महुआ पर लोकसभा में सबसे पहले लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे राजनीति में आने के पहले एस्सार उद्योग समूह में उच्चाधिकारी थे। कहानी का यह तीसरा पात्र २००९ में पहली बार लोकसभा में आया था। झारखंड की सियासत में विवादों के बादल निशिकांत के आसपास हमेशा से तैरते रहे हैं। २०१४ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो निशिकांत ने मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। तब से वे लगातार अपनी यह कोशिश जारी रखे हुए हैं। लेकिन २०१९ में तीसरी बार लोकसभा में चुन कर आने के बावजूद अब तक उन्हें मंत्री नहीं बनाने की वजह सिफर्ध प्रध ानमंत्री को मालूम है।

निशिकांत ने आरोप लगाया है कि महुआ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के मकसद से अडानी समूह के खिलाफ संसद में सवाल पूछे। उनका कहना है कि महुआ ने इसके लिए हीरानंदानी समूह से कई फायदे तो लिए ही, पैसे भी लिए। अपने पर लगे आरोपों के जवाब में महुआ ने निशिकांत पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया है। निशिकांत ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिख कर कहा है कि महुआ ने सांसद के नाते मिले विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया है और उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म की जानी चाहिए। दर्शन हीरानंदानी ने लोकसभा की आचार समिति को दिए अपने हलफनामे में कहा है कि महुआ ने अपने अधिकृत संसदीय एकाउंट की लॉग-इन आईडी का पासवर्ड उन्हें दिया था ताकि वे सवाल सीधे ही लोकसभा सचिवालय को भेज सकें। महुआ का कहना है कि दो-तीन दिन पहले तो हीरानंदानी समूह ने सार्वज. निक बयान दिया था कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अब दर्शन से यह हलफनामा प्रधानमंत्री कार्यालय ने दबाव डाल कर दाखिल कराया है। उन्हें धमकी दी गई कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उनके सारे सरकारी ठेके रद्द कर दिए जाएंगे और समूह का पूरा कारोबार चौपट हो जाएगा।

किघ्स्से की चौथी किरदार पत्रकार सुचेता दलाल हैं। पिछले चालीस साल में उन्होंने इकॉनामिक टाइम्स, बिजिनेस स्टेंडर्ड और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई अखबारों में बतौर वित्तीय पत्रकार काम किया है। उन्होंने हर्षद मेहता शेयर घोटाला, एनरॉन घोटाला, आईडीबीआई बैंक घोटाला और केतन पारीख शेयर घोटाला उजागर करने जैसे धमाके किए हैं। वे पद्मश्री से सम्मा. नित हैं। पिछले १७ साल से वे अपने पति द्वारा संचालित पत्रिका 'मनी लाइफ' के लिए लिखती हैं। सुचेता ने अडानी समूह की कई गड़बडियों को उजागर करने वाली विस्तृत खबरें लिखी हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वे अडानी के खिघ्लाफ सवाल पूछने में महुआ को सक्रिय मदद कर रही थीं। मगर सुचेता का कहना है कि वे और महुआ तो एक-दूसरे को जानते तक नहीं हैं।

कारोबारी संसार की इस घनचक्करी भूलभुलैया में कई खुरपेंच हैं। यह अनायास नहीं है कि पिछले कुछ दशकों में हमारे निर्वाचित और नामजद जनप्रतिनिधियों की जाजम का रंग तेजी से बदला है। एक वक्घ्त समाज सेवा, शिक्षा-जगत और कृषि से जुड़े लोगों का अनुपात संसद और विधानसभाओं में अच्छा-खासा हुआ करता था। अब इन हलकों से आने वाले हाशिए पर हैं। पिछले कुछ दशकों से राजनीति के निर्वाचित दरीचे और समूचे सांगठनिक कैनवस पर कारोबारी विद्याओं में माहिर पेशेवर विशेषज्ञ काबिज होते जा रहे हैं। वे पश्चिमी दुनिया के बड़े-छोटे वित्तीय संस्थानों के छोटे-बड़े पदों पर काम करते हुए सियासत में घुसे हैं। वे निजी कॉरपोरेट संस्थानों की ध्रुव-कुर्सियां संभालने के बाद राजनीति के मंच पर अवतरित हुए हैं। वे अलग-अलग अदालतों में कॉरपारेट दुनिया के अपने मुवक्किल-बादशाहों को 'न्याय दिलाने' के लिए बतौर उनके वकील लड़ते-लड़ते लोकतंत्र के अलग-अलग मंदिरों में पुज. ारी बने हैं। वे आर्थिक विषयों और आंतरिक तथा बाह्य सुरक्षा संबंधी प्रशासनिक जिघ्म्मेदारियों का निर्वाह-कुनिर्वाह करने का अनुभव ले कर राजनीति पर कब्जा करने आए हैं।

इसलिए महुआ मोइत्रा कितनी ही पाक-दामन हों, उन पर लगे छींटे हंगामा मचा रहे हैं। आप उलट कर पूछ सकते हैं कि उन पर पैसे ले कर सवाल पूछने का इल्जाम लगाने वाले अडानी के हजारों करोड़ रुपए की रहस्यमयी आवाजाही पर खामोश क्यों हैं? आप गौतम अडानी से दर्शन हीरानंदन की अदावत के पीछे के कारण भी गिना सकते हैं। आप निशिकांत दुबे के नैतिक इतिहास पर भी प्रश्न खड़े कर सकते हैं।

बच्चों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं ये पेय पदार्थ, जानिए इनकी रेसिपी

आजकल मार्केट में ऐसे कई पेय पदार्थ मौजूद हैं, जिनकी पैकिंग पर हेल्दी और न्यूट्रीशियस जैसे शब्द लिखे होते हैं। हालांकि, इनमें से अधिकतर पेय पदार्थों में आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फिर आर्टिफिशियल रंग के साथ-साथ कई चीजें शामिल होती हैं, जो कि बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे पेय पदार्थों की रेसिपी बताते हैं, जिनका सेवन बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए लाभदायक साबित हो सकता है।

टैंगी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक

इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स सोडियम, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कई विटामिन्स से समृद्ध होती हैं, जो बच्चों की सेहत के लिए लाभदायक हैं। घर पर टैंगी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले एक जार में आधा कप ताजा संतरे का जूस, एक चौथाई कप ताजा नींबू का रस, दो कप फिल्टर पानी या फिर नारियल का पानी अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण में दो चम्मच शहद और एक चुटकी काला नमक मिलाएं, फिर बच्चे को इसका सेवन करवाएं।

कूल कोकोनट ड्रिंक

कूल कोकोनट ड्रिंक की मुख्य सामग्री नारियल पानी है, जो विटामिन-सी, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसलिए इससे बने पेय पदार्थ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। कूल कोकोनट ड्रिंक बनाने के लिए एक जार में तीन कप नारियल का पानी, एक कप सामान्य पानी, आधा कप ताजा नींबू का रस, दो चम्मच शहद और एक चुटकी नमक मिलाएं, फिर बच्चों को इसका सेवन करवाएं।

स्ट्रॉबेरी और नारियल पानी की ड्रिंक

इसके लिए सबसे पहले एक ब्लेंडर के जार में तीन कप नारियल पानी, एक कप स्ट्रॉबेरी, एक कप पानी, आधी छोटी चम्मच सी सॉल्ट और दो बड़ी चम्मच शहद या फिर मेपल सिरप डालकर सभी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर दें। इसके बाद बच्चों को यह पेय पदार्थ गिलास में डालकर परोसें। स्ट्रॉबेरी और नारियल के पानी से बनाई गई कई ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स से युक्त है, जो बच्चों के लिए जरूरी हैं।

कीवी का जूस

कीवी विटामिन-सी, डाइटरी फाइबर और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण का बेहतरीन स्त्रोत है, इसलिए बच्चों के लिए कीवी के जूस का सेवन करना भी लाभदायक है। कीवी का जूस बनाने के लिए सबसे पहले दो से तीन कीवी को धोकर काट लें और इन्हें आधा गिलास पानी, पुदीने के कुछ पत्तों, अदरक के रस, स्वादानुसार शहद और चुटकी भर काले नमक के साथ मिक्सर में डालकर अच्छे से पीसें। इसके बाद छलनी से जूस को गिलास में छानकर बच्चों को पिलाएं।

क्या आप जानते हैं?

न्यजबाइट्स प्लस (बोनस इंफो)

ध्यान रखें कि बच्चों को कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, कैफीन पेय पदार्थ, पैकेज्ड फलों का रस, पैकेज्ड स्मूदी या फिर शेक आदि का सेवन करवाना गलत है क्योंकि इनसे बच्चों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और वह कई बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं।

लेदर के फर्नीचर की सफाई करते समय भूल से भी न करें ये गलतियां

लेदर का फर्नीचर तभी लंबे समय तक ठीक रह सकता है, जब उसकी सफाई बेहतर तरीके से की जाए। हालांकि, कई लोगों से लेदर के फर्नीचर की सफाई करते समय अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिनकी वजह से मेहनत से की गई सफाई पर न सिर्फ पानी फिर सकता है बल्कि लेदर का फर्नीचर भी खराब हो सकता है। आइए आज हम आपको ऐसी ही कुछ सामान्य गलतियों के बारे में बताते हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए।

लेबल के अनुसार सफाई न करना

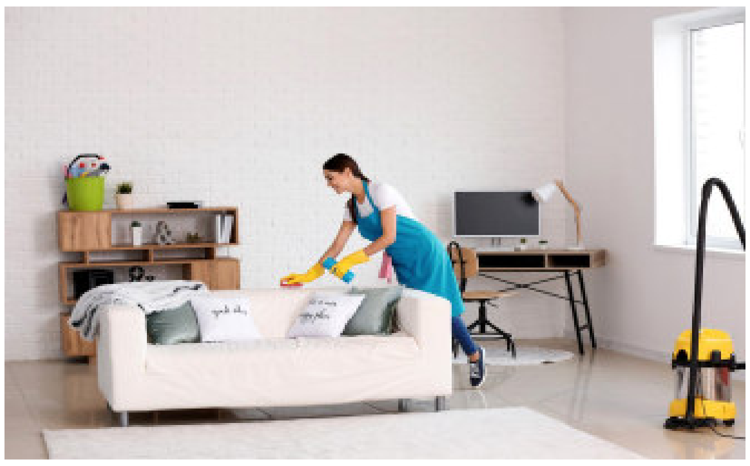

अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका लेदर का फर्नीचर जल्दी खराब हो तो इस पर लगे लेबल के दिशानिर्देशों के अनुसार ही इसकी साफ-सफाई करना सुनिश्चित करें। दरअसल, लेबल पर लिखी जानकारी आपके लेदर के फर्नीचर को लंबे समय तक के लिए नया जैसा बनाए रखने में काफी मददगार साबित हो सकता है। हालांकि, अगर आपके फर्नीचर पर कोई लेबल लगा हुआ नहीं है तो जहां से आपने उसे खरीदा है वहीं से इसकी सफाई से संबंधित जानकारी लें।

सिर्फ पानी का इस्तेमाल करना है गलत

कई लोग लेदर के फर्नीचर की सफाई के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। दरअसल, पानी से लेदर का फर्नीचर बहुत जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए अगर आपने हाल ही नया लेदर का फर्नीचर लिया है तो ऐसी गलती न करें। बेहतर होगा कि आप पानी की जगह लेदर क्लीनर से अपने लेदर के फर्नीचर को साफ करें। यह न सिर्फ आपके लेदर के फर्नीचर को साफ करेगा बल्कि उनमें चमक भी बनाए रखेगा।

हार्ड ब्रश पहुंचा सकता है नुकसान

रोजाना लेदर के फर्नीचर की धूल-मिट्टी को साफ करना जरूरी है, लेकिन डस्टिंग के लिए हार्ड ब्रश का इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती है क्योंकि हार्ड ब्रश से लेदर के फर्नीचर पर खरोंच लग जाती है और फर्नीचर बेकार दिखने लगता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप लेदर के फर्नीचर को साफ करने के लिए सॉफ्ट ब्रश का ही इस्तेमाल करें। अगर आपके पास सॉफ्ट ब्रश न हो तो आप एक मुलायम कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं।

धूप में लेदर के फर्नीचर को रखना है गलती

अगर आप अपने लेदर के फर्नीचर को लंबे समय तक के लिए नया जैसा बनाए रखना चाहते हैं तो उसको धूप की पहुंच से दूर रखें क्योंकि धूप के प्रभाव से फर्नीचर का रंग हल्का पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त, धूप के प्रभाव से लेदर के फर्नीचर में क्रैक्स आने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए लेदर के फर्नीचर को धूप में रखने से बचें और इसके साथ ही लेदर के फर्नीचर की रोजाना कंडीशनिंग करें।

चाय और कॉफी में चीनी की जगह इन चीजों का कर सकते हैं इस्तेमाल

कई लोग अपने दिन की शुरूआत चाय या फिर कॉफी के सेवन से करना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें मिलाई जाने वाली चीनी स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसी वजह से अगर आप चाय और कॉफी में मिठास के लिए चीनी की जगह कुछ अन्य विकल्प खोज रहे हैं तो यह लेख आपके लिए ही है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि चाय और कॉफी में चीनी की बजाय किन चीजों को मिलाया जा सकता है।

मेपल सिरप

मेपल सिरप कई तरह के मिनरल्स और विटामिन्स के साथ-साथ एंटी-ऑक्सीडेंट गुण से समृद्ध होता है। यहीं नहीं, इसमें कैलोरी की मात्रा भी बहुत कम होती है, इसलिए इसे चीनी का एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प माना जाता है। आप चाहें तो अपनी चाय या कॉफी में चीनी की जगह मेपल सिरप को मिलाकर उनका स्वाद बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप मेपल सिरप को कई तरह के मीठे व्यंजनों का हिस्सा बना सकते हैं।

गुड़

गुड़ भी चीनी का एक स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है क्योंकि इसका सेवन भी स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। गुड़ में आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और कार्बोहाइड्रेट जैसे कई पोषक तत्व के साथ-साथ एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण और एंटी-एलर्जिक गुण आदि शामिल होते हैं, इसलिए इसे स्वास्थ्य के लिए बेहतर माना जाता है। आप चाहें तो अपनी चाय या कॉफी के लिए गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ध्यान रखें कि गुड़ को चाय और कॉफी को बनाने के बाद डालना है।

कोकोनट शुगर

आजकल बाजार में कई तरह की चीनी मौजूद है, जिनमें कोकोनट शुगर यानी नारियल से बनी हुई चीनी भी शामिल है। यह चीनी कई तरह के पोषक तत्वों से समृद्ध होती है, इसलिए इन दिनों यह काफी प्रचलन में है और फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए अच्छी मानी जा रही है। इसलिए अगर आप चाहें तो अपनी चाय और कॉफी में कोकोनट शुगर को मिलाकर उनकी मिठास बढ़ा सकते हैं।

शहद

शहद एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि है क्योंकि इसमें कई प्रकार के खनिज व पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें एंटी-इंफेक्शन, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-ऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होते हैं, इसलिए इसे चाय या फिर कॉफी में चीनी की जगह मिलाना काफी अच्छा विचार हो सकता है। इससे न सिर्फ इन चीजों में मिठास आएगी बल्कि यह कई तरह से स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आप चाहें तो स्मूदी और शेक आदि में भी शहद को मिला सकते हैं।

कुमाऊं सहकारी संघ को नई कार्यकारिणी गठित, बबिता मेहरा बनी निर्विरोध अध्यक्ष

अल्मोड़ा। कुमाऊं सहकारी संघ लिमिटेड की नई कार्यकारिणी के गठन के लिए आयोजित चुनाव प्रक्रिया निर्विरोध संपन्न हुई। सभी पदों पर एक-एक नामांकन पत्र दाखिल होने के कारण निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का फूल-मालाओं से स्वागत किया गया और मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। चुनाव परिणाम के अनुसार बबिता मेहरा संघ की अध्यक्ष तथा मीनाक्षी पांडे उपाध्यक्ष निर्वाचित हुईं। इसके अलावा गोपाल सिंह, रविन्द्र खोलिया, आनंद सिंह, पप्पू मेहरा, चंदन सिंह, सुरेन्द्र सिंह भोजक और हयात सिंह विभिन्न सहकारी समितियों के प्रतिनिधि के रूप में निर्विरोध चुने गए। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सभी प्रतिनिधियों ने आपसी सहमति से प्रत्येक पद के लिए केवल एक-एक नामांकन प्रस्तुत किया। किसी भी पद पर मुकाबला नहीं होने से मतदान की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रतिनिधियों ने इसे सहकारिता की मजबूत परंपरा, संगठनात्मक एकजुटता और आपसी विश्वास का प्रतीक बताया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष बबिता मेहरा ने सभी प्रतिनिधियों और सहकारी समितियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह पारदर्शिता और समर्पण के साथ दायित्व निभाएंगी। उन्होंने सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने, किसानों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने तथा सदस्य समितियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष एवं जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ललित लटवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष महेश नयाल, रानीखेत जिलाध्यक्ष घनश्याम भट्ट, नगर अध्यक्ष विनीत बिष्ट, भाजपा बागेश्वर के जिला महामंत्री घनश्याम जोशी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सूरज सिराड़ी, जिला पंचायत सदस्य प्रेम लटवाल, आनंद कनवाल, हृदेश मेहरा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सहकारी समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

एनएमसी मान्यता के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज की तैयारी तेज

रुद्रपुर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) से एमबीबीएस सीटों की मान्यता नहीं मिलने के बाद मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राजकीय मेडिकल कॉलेज की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीडीओ, मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य, कार्यदायी संस्था, प्रोजेक्ट प्रबंधक, ठेकेदार और अन्य अधिकारियों ने निर्माण कार्य और एनएमसी की ओर से बताई गई कमियों पर विस्तार से चर्चा की। जिलाधिकारी ने शेष निर्माण कार्य और आवश्यक व्यवस्थाएं अगले 15 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि दोबारा निरीक्षण से पहले सभी कमियां दूर की जा सकें। एनएमसी की निरीक्षण रिपोर्ट में फैकल्टी की भारी कमी, अधूरी आधारभूत संरचना और आवश्यक संसाधनों की कमी सामने आई थी।

मान्यता के लिए न्यूनतम 81 फैकल्टी सदस्यों की आवश्यकता है, जबकि निरीक्षण के समय कॉलेज में अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा भवन निर्माण, पुस्तकालय, छात्रावास और अस्पताल की व्यवस्थाएं भी निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाई गईं। इसी आधार पर फिलहाल एमबीबीएस सीटों की मान्यता नहीं दी गई। मेडिकल कॉलेज प्रशासन के अनुसार, एनएमसी के नियमों के तहत कॉलेज के पास अभी दो अवसर शेष हैं। पहली अपील 15 दिनों के भीतर की जाएगी, जिसके बाद एनएमसी की टीम दोबारा निरीक्षण करेगी। यदि उस निरीक्षण में भी कमियां मिलती हैं तो रिपोर्ट के बाद फिर 15 दिनों के भीतर अपील का एक और अवसर मिलेगा। इसके बाद अंतिम निरीक्षण कर एनएमसी अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी करेगी।मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉ.उषा रावत ने बताया कि फैकल्टी की कमी दूर करने के लिए निदेशालय को प्रोफेसर और अन्य शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव भेजा गया है। वर्तमान में कॉलेज में 22 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि नौ अन्य शिक्षकों के चयन परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। अगले सप्ताह से इंटरव्यू शुरू कर फैकल्टी की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। बैठक में बताया गया कि फर्नीचर का लगभग 20 प्रतिशत कार्य शेष है, जबकि प्रशासनिक भवन, छात्रावास सहित अन्य निर्माण कार्य करीब 90 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं।

बारिश और भूधंसाव से टूटे रास्ते, समय पर मरम्मत बड़ी चुनौती

चमोली। मां नंदा देवी की बड़ीजात की तैयारियों के बीच लगातार हो रही बारिश बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। यात्रा मार्गों की मरम्मत और यात्रा पड़ावों पर चल रहे विकास कार्य बारिश के कारण प्रभावित हो रहे हैं। कई स्थानों पर पैदल मार्ग अभी तक बदहाल हैं। जहां मरम्मत कार्य शुरू हुआ था वहां भूधंसाव होने से हालात चिंताजनक बने हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते रास्ते दुरुस्त नहीं किए गए तो श्रद्धालुओं और मां नंदा की डोली को टूटे और जोखिम भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा।इस वर्ष मां नंदा देवी की बड़ीजात 5 से 30 सितंबर तक होगी। यात्रा ककेलिए कुरुड़ से लेकर बधाण क्षेत्र में तैयारियां तेज हैं। जिला पंचायत, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से यात्रा पड़ावों पर वाहन पार्किंग, शौचालय, पथ प्रकाश, पेयजल व्यवस्था और पैदल मार्गों के निर्माण व सुधारीकरण का कार्य कराया जा रहा है लेकिन रुक-रुक कर हो रही बारिश से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। नंदानगर विकासखंड के तेलाण से बंगाली-सुपताल पैदल मार्ग के करीब पांच किमी हिस्से में लोनिवि कर्णप्रयाग की ओर से सुधारीकरण कार्य कराया जा रहा है। हालिया बारिश के बाद इस मार्ग के कई हिस्से भूधंसाव की चपेट में आ गए हैं जिससे निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ है।

सेवा पखवाड़ा शिविर में 295 को योजनाओं का लाभ

बागेश्वर। राज्य सरकार के श्सेवा, सुशासन एवं समर्पणश एवं श्जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारश अभियान के तहत मंगलवार को इंटर कॉलेज क्वैराली में सेवा पखवाड़ा शिविर आयोजित किया गया। विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और पात्र लोगों को मौके पर ही लाभान्वित किया। शिविर में 360 लोगों ने भाग लिया, जिनमें 295 लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। 46 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि 14 प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन प्राप्त हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। दर्जा राज्यमंत्री शिव सिंह बिष्ट ने नागरिकों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। तहसीलदार ऋतु गोस्वामी, निदेशक कुमाउं मंडल विकास निगम दयाल सिंह ऐठानी, प्रधानाचार्य गिरीश चंद्र, ग्राम प्रधान चामी सुंदर लाल, ग्राम प्रधान क्वैराली हरीश प्रसाद, ग्राम प्रधान अमसरकोट गिरीश सिंह टंगड़िया रहे।

बेहड़ ने शिक्षा मंत्री से मिलकर 15 विद्यालयों के उच्चीकरण की मांग दोहराई

रुद्रपुर। विधायक तिलकराज बेहड़ ने देहरादून में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से मुलाकात कर किच्छा क्षेत्र के 15 राजकीय विद्यालयों के उच्चीकरण की मांग दोहराई। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावित विद्यालयों के उच्चीकरण पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। मंगलवार को हुई मुलाकात में बेहड़ ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धौराडाम, सिरौली, रामेश्वरपुर, गिद्धपुरी, किच्छा, खमरिया और छिनकी को हाईस्कूल तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बब्बरपुर, तुर्कागौरी, रामनगर, पंतपुरा, नगला और भंगा के साथ ही राजकीय उच्च विद्यालय किच्छा को इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकृत करने की मांग रखी। इसके अलावा उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय आनंदपुर को उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाने का भी अनुरोध किया। बेहड़ ने बताया कि उन्होंने दो मई 2023 को भी इस संबंध में पत्र भेजा था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पिछले 20 वर्षों से किसी भी राजकीय विद्यालय का उच्चीकरण नहीं हुआ है, जबकि आबादी लगातार बढ़ रही है। इसके कारण हाईस्कूल और इंटर कॉलेजों में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को हर वर्ष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों के उच्चीकरण से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के हजारों छात्र-छात्राओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए दूसरे स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा।

हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के काम 20 जुलाई तक पूरे करें

हरिद्वार। कांवड़ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे प्रशासन ने हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के सभी निर्माण कार्य 20 जुलाई तक पूरे करने के निर्देश दिए हैं। डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, गुणवत्ता बनाए रखने और विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंगलवार को डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों के साथ हिल बाईपास, सप्तऋषि क्षेत्र, रोड़ी बेलवाला मैदान और नजीबाबाद हाईवे का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि हाईवे, कांवड़ पटरी और आंतरिक मार्गों के सभी निर्माण कार्य 20 जुलाई तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। इसके बाद सड़कों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होगा। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करने के भी निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान पार्किंग, यातायात प्रबंधन, बैरिकेडिंग, सड़क मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को मेले से

स्वामी/प्रकाशक/मुद्रक/सम्पादक **गार्गी मिश्रा** द्वारा इंटर ग्राफिक आफॅसेट प्रिंटर्श 64 नेशविला रोड़ देहरादून, उत्तराखंड से मुद्रित, 98, 2-फ्लोर, सनशाइन अपार्टमेन्ट, नागल हटनाला, कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून - 248001 से प्रकाशित।

सम्पादकः
गार्गी मिश्रा
8765441328

समस्त विवाद देहरादून न्यायालय के अधीन होंगे।